



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08102021-230260  
CG-MH-E-08102021-230260

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]

No. 441]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### अधिसूचना

मुंबई, 21 सितम्बर, 2021

**सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) (पूर्व में पोत परिवहन मंत्रालय) के पत्र सं. पीडी-13/1/2018-पीपीपी प्रकोष्ठ दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसरण में डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी के सामान्य कार्गो बर्थ में कोकिंग कोयले तथा स्टीम कोयले के अभियंत्रित प्रहस्तन के लिए विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्रा. लि. (वीजीसीबीपीएल) से संबंधित आदेश सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित युक्तिकृत भंडारण प्रभारों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख में संशोधन के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

### महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

**सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी**

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

- - -

आवेदक

### कोरम

- (i). श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

## आदेश

(सितंबर, 2021 के 15वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने स्ट्रेस्ड पीपीपी परियोजनाओं पर पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएडब्ल्यू) (पूर्व में पोत परिवहन मंत्रालय) के पत्र सं. पीडी-13/1/2018-पीपीपी प्रकोष्ठ दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसारण में और डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी के सामान्य कार्गो बर्थ में कोकिंग कोयला तथा स्टीम कोयला के अभियंत्रिकरुत प्रहस्तन के लिए विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्रा. लि. (वीजीसीबीपीएल) के नाम में दरमान (एसओआर) अधिसूचित करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा अनुमोदित भंडारण प्रभारों के युक्तिकरण के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के प्रस्ताव के आधार पर आदेश सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 पारित किया था। उक्त आदेश राजपत्र सं. 296 दिनांक 21 अगस्त 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था। भंडारण प्रभार का युक्तिकरण इस प्राधिकरण द्वारा 21 जनवरी 2019 से अनुमोदित किया गया था और एक वर्ष के लिए अर्थात् 20 जनवरी 2020 तक वैध था।

1.2. आदेश सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 की अनुसूची 4 में लागू भंडारण प्रभार को बदलते हुए आदेश दिनांक 24 जुलाई 2019 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित युक्तिसंगत भंडारण प्रभार नीचे दिया गया है:-

“

(रु. में प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग)

क्र.सं.	विवरण	लागू सूचकांकन के बाद वर्ष 2018-19 के लिए लागू भंडारण प्रभार	लागू सूचकांकन के बाद वर्ष 2019-20 के लिए लागू मौजूदा भंडारण प्रभार	21.1.2019 से 31.3.2019 तक संशोधित भंडारण प्रभार	1.4.2019 से 20.1.2020 तक संशोधित भंडारण प्रभार
1.	भंडारण प्रभार (0-10 दिन)	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
2.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	2.06	2.11	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
3.	भंडारण प्रभार (16-20 दिन)	4.11	4.21	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
4.	भंडारण प्रभार 21वें दिन से आगे	8.22	8.43	8.22	8.43

## टिप्पणियां:

- 20 निःशुल्क दिवस स्वीकृत किए जाएंगे। निःशुल्क अवधि पोत कार्गो की उतराई पूरी होने के दिन के अगले तदन से शुरू होगी। निःशुल्क अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए, सीमाशुल्क अधिसूचित अवकाश दिवस और टर्मिनल के गैर-कार्यदिवस इससे अतिरिक्त होंगे।
- भंडारण प्रभार निर्धारित निःशुल्क दिनों के बाद टर्मिनल के गैर-कार्यदिवसों और कार्गो के विराम के लिए सीमाशुल्क अधिसूचित अवकाश दिवसों सहित सभी दिनों के लिए देय होंगे।
- कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए प्रोद्भूत नहीं होगा जब टर्मिनल परिचालक तब कार्गो की डिलीवरी/नौभरण करने की स्थिति में नहीं हो जब टर्मिनल परिचालक पर आरोप्य कारणों की वजह से अनुरोध किया गया हो।
- उपर्युक्त भंडारण अनुसूची 20 जनवरी 2020 तक वैध रहेगी और यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी तथा उपयुक्त सूचकांकन दरों के साथ आदेश दिनांक 11 जनवरी 2013 में यथा अनुमोदित मूल भंडारण अनुसूची 21 जनवरी 2020 से लागू होगी, जब तक कि वीपीटी द्वारा समीक्षा और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।”

2.1. उक्त आदेश दिनांक 24 जुलाई 2019 के संदर्भ में, वीपीटी अपने ईमेल दिनांक 12 मई 2021 द्वारा स्ट्रेस्ड परियोजना के भंडारण प्रभारों की वसूली के लिए प्रभावी तारीख के लागू होने में संशोधन के लिए अपने पत्र सं. आईआरएनपी/स्टैंड/वीजीसीबी/2020 दिनांक 05 फरवरी 2021 द्वारा प्रस्ताव लेकर आया था। वीपीटी ने उक्त आदेश में अनुमोदित 21 जनवरी 2019 की बजाय सभी महापत्तनों को स्ट्रेस्ड पीपीपी परियोजनाओं पर तत्कालीन एमओएस द्वारा जारी निदेशों की तारीख 11 जुलाई 2018 से भंडारण प्रभार के युक्तिकरण के लागू होने की तारीख से संशोधन करने का अनुरोध किया था।

2.2. वीपीटी द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा अनुमोदित वीजीसीबीपीएल की स्ट्रेस्ड परियोजना के भंडारण प्रभार के युक्तिकरण के लिए प्रभावी तारीख 11 जुलाई 2018 के कार्यान्वयन में संशोधन के लिए अपने प्रस्ताव में वीपीटी द्वारा कही गई मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-

- एमओपीएसडब्ल्यू ने “स्ट्रेस्ड परियोजना” के रूप में महापत्तनों में पीपीपी परियोजना की पहचान करने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश और इसके पत्र सं. पीडी-13/1/2018-पीपीपी प्रकोष्ठ दिनांक 11.07.2018 द्वारा उसपर राहत देने के लिए अंगीकृत किए जाने की प्रक्रिया।
- एमओपीएसडब्ल्यू दिशानिर्देशों के आधार पर, वीपीटी बोर्ड ने वीपीटी में परिचालन करने वाले वीजीसीबीपीएल की “स्ट्रेस्ड परियोजना” के रूप में पहचान की थी, दो स्पैल अर्थात् (i) टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24.07.2019 द्वारा 21.01.2019 से 20.01.2020 और (ii) टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/14/2020-वीपीटी दिनांक 01.06.2020 में भंडारण अनुसूची संशोधित करते हुए उपलब्ध करवाई गई राहत।
- वीजीसीबीपीएल ने एमओपीएसडब्ल्यू को संबोधित अपने पत्र दिनांक 02.11.2020 (प्रतिलिपि प्रेषित) द्वारा भंडारण प्रभारों के युक्तिकरण के लिए यथा लागू तारीख रूप में 11.07.2018 (एमओपीएसडब्ल्यू दिशानिर्देश की अधिसूचना की तारीख) पर विचार करने का अनुरोध किया था; दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के न्यासी बोर्ड का निर्णय उद्धरित करते हुए, जिसमें मैं, अदानी कांडला बल्क टर्मिनल प्रा. लि. के मामले में प्रशुल्क युक्तिकरण अनुमोदित किया था और 11.07.2018 से लागू किए जाने की अनुशंसा की थी।

- (iv). यह मामला समीक्षा और विचार करने के लिए 29.12.2020 को आयोजित बैठक में वीपीटी बोर्ड के सामने रखा गया था। वीपीटी बोर्ड ने इस मुद्दे पर विचार किया था और वीपीटी बोर्ड संकल्प सं. 147/2020-21 (2020-21 की बैठक सं. 4) दिनांक 29.12.2020 (प्रतिलिपि प्रेषित) द्वारा निम्नलिखित का संकल्प लिया था:
- (क). भंडारण प्रभारों के युक्तिकरण की प्रभावी तारीख 11.07.2018, वह तारीख जिसको मंत्रालय ने स्ट्रेस्ड पीपीपी परियोजनाओं पर दिशानिर्देश संप्रेषित किया था, के कार्यान्वयन के लिए मै. वीजीसीबीपीएल के अनुरोध पर विचार करना।
- (ख). परस्पर रूप से सहमत तारीख को खण्ड-14 (viii) में टीएमपी आदेश दिनांक 24.07.2019 के अनुसार मंत्रालय के दिशानिर्देश दिनांक 11.07.2018 के जारी होने की तारीख से भंडारण अनुसूची में संशोधन पर टीएमपी को सूचित करना और
- (ग). तदनुसार रियायतकर्ता मै. वीजीसीबीपीएल को सूचित करना।
- (v). इसके अलावा, 28.12.2020 को हुई समीक्षा बैठक के दौरान, माननीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने एमओपीएसडब्ल्यू पत्र सं. पीडी-13/53/2020-पीपीपी (पार्ट-5)/ई-344240 दिनांक 06.01.2021 (प्रतिलिपि प्रेषित) द्वारा समान मामले में डीपीटी द्वारा अंगीकृत कार्यविधि तथा प्रक्रिया के अनुसार मामले को सुलझाने का निदेश दिया था।
- (vi). उपर्युक्त के मद्देनजर, वीपीटी ने अपने पत्र सं. पीडी-13/1/2018-पीपीपी प्रकोष्ठ दिनांक 11.07.2018 द्वारा 11.07.2018 से लागू संप्रेषित दिशानिर्देशों के आधार पर परिगणित संशोधित भंडारण अनुसूची की समीक्षा तथा अधिसूचित करने का अनुरोध किया था।

2.3. चूंकि वीपीटी का प्रस्ताव केवल युक्तिसंगत भंडारण प्रभार के कार्यान्वयन के लागू होने की तारीख में संशोधन है, इसलिए परामर्श/संयुक्त सुनवाई जरूरी नहीं पाया गया है।

3.1. यहाँ पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश दिनांक 24 जुलाई 2019 वीपीटी के तत्कालीन आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2018 पर आधारित था जिसमें न्यासी बोर्ड ने दो वर्षों अर्थात् 2016-17 और 2017-18 के वास्तविक आंकड़ों पर विचार करते हुए एमओपीएसडब्ल्यू पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 में निर्धारित तीन मानदंड के आधार पर स्ट्रेस्ड परियोजना के रूप में वीजीसीबीपीएल को अंगीकृत किया था।

3.2. उक्त प्रश्नुक्त आदेश दिनांक 24 जुलाई 2019 की कार्यवाही के दौरान, वीजीसीबीपीएल ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि युक्तिसंगत भंडारण प्रभार के प्रभाव का परिकलन करने के लिए परस्पर रूप से सहमत प्रभावी तारीख के लिए रियायतकर्ता और रियायतप्रदाता प्राधिकरण दोनों से जरूरी कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।

3.3. वीजीसीबीपीएल द्वारा कही गई उक्त बात के संबंध में, इस प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 24 जुलाई 2019 के पैरा 14 (viii) में कहा गया है कि एमओएस ने स्ट्रेस्ड पीपीपी परियोजनाओं पर सभी महापत्तनों को पत्र सं. पीडी-13/1/2018-पीपीपी प्रकोष्ठ दिनांक 11 जुलाई 2018 जारी किया था। एमओएस का उक्त पत्र एमओएस द्वारा निर्धारित स्ट्रेस्ड परियोजना के लिए मानदंड के आधार पर स्ट्रेस्ड परियोजना के संबंध में रियायतकर्ता के साथ परामर्श से भंडारण प्रभारों के युक्तिकरण के लिए उपयुक्त प्रस्ताव दाखिल करे। वीपीटी ने प्रस्ताव दिनांक 7 दिसंबर 2018 दाखिल किया था। इस प्राधिकरण ने 21 जनवरी 2019 अर्थात् वह तारीख जब से वीपीटी के प्रस्ताव को इस प्राधिकरण द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया था, से निःशुल्क अवधि तथा युक्तिसंगत भंडारण प्रभार में वृद्धि करने के लिए वीपीटी प्रस्ताव अनुमोदित किया था। चूंकि वीपीटी के बोर्ड ने एक वर्ष के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया था और उसके बाद समीक्षा करने के लिए आदेश दिनांक 24 जुलाई 2019 में संशोधित भंडारण अनुसूची की वैधता इस प्राधिकरण द्वारा 21 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2020 तक एक वर्ष के लिए अनुमोदित किया गया था।

युक्तिसंगत भंडारण प्रभार के लिए परस्पर सहमत प्रभावी तारीख के लिए रियायतकर्ता और रियायतप्रदाता प्राधिकरण दोनों को पूछते हुए जरूरी कार्यवाही करने के लिए इस प्राधिकरण को वीजीसीबीपीएल द्वारा कही गई बात के संबंध में, इस प्राधिकरण ने दिया था कि यह इस मामले को देखने के लिए वीपीटी तथा वीजीसीबीपीएल के लिए है।

4.1. इस परिप्रेक्ष्य में, वीपीटी ने आदेश दिनांक 24 जुलाई 2019 में अनुमोदित 21 जनवरी 2019 की बजाय 11 जुलाई 2018 रूप में सुनवाई की प्रभावी तारीख में संशोधन के लिए मौजूदा प्रस्ताव दाखिल किया था। वीपीटी प्रस्ताव युक्तिसंगत भंडारण प्रभार के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख की समीक्षा के लिए वीजीसीबीपीएल द्वारा किए गए अनुरोध पर आधारित है और डीपीटी अर्थात् अदानी कांडला बल्क टर्मिनल प्रा. लि. (एकेबीटीपीएल) के समान मामले में अंगीकृत प्रक्रिया के अनुसार वीजीसीबीपीएल के लिए युक्तिसंगत भंडारण प्रभारों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख के संबंध में मुद्दे को हल करने के लिए वीपीटी को निदेश देते हुए वीपीटी को एमओपीएसडब्ल्यू पत्र दिनांक 06 जनवरी 2021 के अनुपालन में है।

4.2. वीपीटी के न्यासी बोर्ड ने 11.07.2018 अर्थात् वह तारीख जिसको एमओपीएसडब्ल्यू ने स्ट्रेस्ड पीपीपी परियोजनाओं पर महापत्तनों को निदेश जारी किए थे, को भंडारण प्रभारों के युक्तिकरण की प्रभावी तारीख के कार्यान्वयन के लिए मै. वीजीसीबीपीएल के अनुरोध पर विचार करने का संकल्प लिया था।

4.3. डीपीटी के समान मामले में दिए गए संदर्भ के संबंध में, यह कहना है कि इस प्राधिकरण ने आदेश सं.टीएमपी/64/2019-डीपीटी दिनांक 01 जून 2020 द्वारा युक्तिकरण के लिए डीपीटी का प्रस्ताव अर्थात् डीपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए 11 जुलाई 2018 से बीओटी परिचालक मै. अदानी कांडला बल्क टर्मिनल प्रा. लि. (एकेबीटीपीएल) द्वारा विकसित शुष्क बल्क टर्मिनल के लिए सूचकांकित भंडारण प्रभारों की कटौती अनुमोदित किया था।

5. चूंकि वीपीटी द्वारा प्रस्तावित आदेश दिनांक 24 जुलाई 2019 में निर्धारित भंडारण प्रभार के युक्तिकरण के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख में संशोधन वीपीटी तथा वीजीसीबीपीएल के बीच परस्पर सहमत है, वीपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित और एमओपीएसडब्ल्यू के निदेशों पर आधारित है, इसलिए यह प्राधिकरण पत्तन द्वारा अब यथा प्रस्तावित आदेश सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा अनुमोदित युक्तिसंगत भंडारण प्रभारों की प्रभावी तारीख 11 जुलाई 2018 संशोधित करता है। उक्त आदेश में अनुमोदित युक्तिसंगत भंडारण प्रभार की वैधता अर्थात् 20 जनवरी 2020 अपरिवर्तित रहेगा।

6.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा अनुमोदित युक्तिसंगत भंडारण अनुसूची की प्रभावी तारीख 11 जुलाई 2019 रूप में संशोधित करता है और निम्नलिखित अनुसूची से बदलता है:

“

(रु. में प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग)

क्र.सं.	विवरण	लागू सूचकांकन के बाद वर्ष 2018-19 के लिए लागू भंडारण प्रभार	लागू सूचकांकन के बाद वर्ष 2019-20 के लिए लागू मौजूदा भंडारण प्रभार	11.7.2018 से 31.3. 2019 तक संशोधित भंडारण प्रभार	1.4.2019 से 30.1. 2020 तक संशोधित भंडारण प्रभार
1.	भंडारण प्रभार (0-10 दिन)	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
2.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	<b>2.06</b>	<b>2.11</b>	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
3.	भंडारण प्रभार (16-20 दिन)	<b>4.11</b>	<b>4.21</b>	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
4.	भंडारण प्रभार 21वें दिन से आगे	<b>8.22</b>	<b>8.43</b>	<b>8.22</b>	<b>8.43</b>

”

6.2. आदेश दिनांक 24 जुलाई 2019 में अनुसूची के अधीन निर्धारित टिप्पणी समान रहती है।

टी. एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा. 313/21-22]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 21st September, 2021

**No. TAMP/9/2019-VPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for amendment in the effective date of implementation of rationalized storage charges approved by this Authority vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 relating to the Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis in pursuance of Ministry of Ports, Shipping and Waterways [MOPSW] (erstwhile Ministry of Shipping) letter No. PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 as in the Order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### Case No. TAMP/9/2019-VPT

Visakhapatnam Port Trust

- - -

Applicant

### QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 15<sup>th</sup> day of September 2021)

This Authority has passed an Order No. TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019, in pursuance of Ministry of Ports, Shipping and Waterways [MOPSW] (*erstwhile Ministry of Shipping*) letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 on Stressed PPP Projects and based on the proposal of Visakhapatnam Port Trust (VPT) for rationalization of the storage charges approved by this Authority vide Order No. TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying Scale of Rates (SOR) in the name of Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis. The said Order was notified vide Gazette No. 296 dated 21 August 2019. The rationalization of storage charge was approved by this Authority from 21 January 2019 and was valid for one year i.e. upto 20 January 2020.

1.2. The rationalized storage charge approved by this Authority in the Order dated 24 July 2019 replacing the storage charge applicable in Schedule 4 of Order No. TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 is given below:

“

(in ₹ per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Particulars	Storage Charges applicable for the year 2018-19 after applicable indexation	Existing Storage Charges applicable for the year 2019-20 after applicable indexation	Amended Storage Charges from 21.1.2019 till 31.3.2019	Amended Storage Charges from 1.4.2019 till 20.1.2020
1.	Storage Charges (0-10 days)	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
2.	Storage Charges (11-15 days)	2.06	2.11	No Charges	No Charges
3.	Storage Charges (16-20 days)	4.11	4.21	No Charges	No Charges
4.	Storage Charges 21 <sup>st</sup> Day onwards	8.22	8.43	8.22	8.43

**Notes:**

- (i). 20 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.
- (ii). Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.
- (iii). Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver/ ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator.
- (iv). The above storage schedule shall be valid till 20 January 2020 and it shall automatically lapse and the original storage schedule as approved in the Order dated 11 January 2013 with appropriate indexation rates shall come into effect from 21 January 2020, unless reviewed by VPT and approved by this Authority."

2.1. With reference to the said Order dated 24 July 2019, the VPT vide its e-mail dated 12 July 2021 has come up with the proposal vide its letter No.IRNP/Std/VGCB/2020 dated 05 February 2021 (received by the office on 12 July 2021) for amendment in implementation of the effective date for rationalization of storage charges of Stressed Project. The VPT has requested to amend the effective date of rationalization of storage charge with effect from 11 July 2018 i.e. the date the then MOS issued directives on stressed PPP projects to all Major Ports instead of 21 January 2019 approved in the said Order.

2.2. The main points made by VPT in its proposal for amendment in implementation of the effective date for rationalization of storage charges of Stressed Project of VGCBPL approved by this Authority vide Order No. TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 as 11 July 2018 are given below:

- (i). MOPSW issued guidelines for identifying PPP project in Major Ports as "stressed project" and the procedure to be adopted for giving relief thereon vide its letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11.07.2018.
- (ii). Based on the MOPSW Guidelines, VPT Board identified VGCBPL, operating in VPT, as 'stressed project', and relief provided by revising storage schedule in two spells i.e., (i) from 21.01.2019 to 20.01.2020 vide TAMP Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24.07.2019 and (ii) from 21.01.2020 to 20.01.2021 vide TAMP Order No.TAMP/14/2020-VPT dated 01.06.2020.
- (iii). VGCBPL, vide its letter dated 02.11.2020 [copy furnished] addressed to MOPSW has requested to consider 11.07.2018 (date of notification of MOPSW Guidelines) as the effective date for rationalisation of storage charges; citing the decision of Board of Trustees of Deendayal Port Trust (DPT), wherein tariff rationalisation was approved and recommended with effect from 11.07.2018 in respect of M/s.Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd.
- (iv). The matter was put up to VPT Board in the meeting held on 29.12.2020 for review and deliberations. VPT Board deliberated on the issue and resolved the following vide VPT Board Resolution No.147/2020-21 (Meeting No. 4 of 2020-21) dated 29.12.2020 [copy furnished]:
  - (a). To consider the request of M/s. VGCBPL for implementation of the effective date of rationalization of storage charges as 11.07.2018, the date on which Ministry communicated the guidelines on Stressed PPP Projects.
  - (b). To inform TAMP on the amendment in the storage schedule from the date of issue of the guidelines of the Ministry dated 11.07.2018 in terms of the TAMP Order dated 24.07.2019 at Clause-14 (viii) on mutually agreeable date and
  - (c). To inform the concessionaire M/s. VGCBPL accordingly.
- (v). Further, during the review meeting held on 28.12.2020, Hon'ble Minister of State of Ports, Shipping & Waterways (I/C) directed to resolve the issue in line with the process and procedure adopted by DPT in a

similar case there; vide MOPSW letter No. PD-13/53/2020-PPP(Part-5)/e-344240 dated 06.01.2021 [copy furnished].

- (vi). In view of the above, the VPT has requested to review and notify the revised storage schedule reckoned based on the guidelines communicated by MOPSW vide its letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11.07.2018 i.e. with effect from 11.07.2018.

2.3. Since the proposal of the VPT is only for amendment in the effective date of implementation of the rationalized storage charge, consultation/ joint hearing is not found necessary.

3.1. It is relevant here to mention that the Order dated 24 July 2019 approved by this Authority was based on the then proposal of VPT dated 7 December 2018 wherein the Board of Trustees had classified the VGCBPL as a stressed project based on three criteria prescribed in the MOPSW letter dated 11 July 2018 considering the actuals for the two years viz. 2016-17 and 2017-18.

3.2. During the processing of the said tariff Order dated 24 July 2019, the VGCBPL had requested this Authority to do the needful asking both the Concessionaire and Concessioneing Authority to have a mutually agreeable effective date for computing the impact of rationalized storage charge.

3.3. With regard to the said point made by VGCBPL, this Authority at para 14 (viii) of Order dated 24 July 2019 has stated that the MOS has issued letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 to all Major Ports on Stressed PPP Projects. The said letter of the MOS requires the Major Port Trusts to file an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaire as regards stressed project based on the criteria for stressed project prescribed by the MOS. The VPT has filed the proposal dated 7 December 2018. This Authority for the reasons stated in the Order approved the VPT proposal for increase in free period and rationalised storage charge with effect from 21 January 2019 i.e. the date from when in principle approval was accorded by this Authority to the proposal of VPT. Since, the Board of VPT had accorded approval to the proposal for one year and to review thereafter, validity of the amended storage schedule in the Order dated 24 July 2019 was approved by this Authority for the period of one year from 21 January 2019 till 20 January 2020.

As regards the point made by the VGCBPL to this Authority to do needful asking both Concessionaire and Concessioneing Authority to have a mutually agreeable effective date for rationalised storage charge, this Authority held that it is for the VPT and the VGCBPL to look into the matter.

4.1. In this backdrop, the VPT has filed the current proposal for amendment in the effective date of hearing as 11 July 2018 instead of 21 January 2019 approved in the Order dated 24 July 2019. The VPT proposal is based on the request made by the VGCBPL for review of effective date of implementation of rationalized storage charge and also in compliance of the MOPSW letter dated 06 January 2021 to VPT directing VPT to resolve the issue regarding effective date of implementation of rationalized storage charges for VGCBPL in line with procedure adopted in similar case of DPT i.e. of Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL).

4.2. The Board of Trustees of VPT has also resolved to consider the request of M/s.VGCBPL for implementation of the effective date of rationalization of storage charges as 11.07.2018 i.e. the date on which MOPSW issued directives to the Major Ports on Stressed PPP Projects.

4.3. As regards the reference drawn to similar case of DPT, it is to state that this Authority vide Order No.TAMP/64/2019-DPT dated 01 June 2020 has approved the proposal of DPT for rationalization i.e. reduction of indexed storage charges for Dry Bulk Terminal developed by the BOT operator M/s.Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL) w.e.f. 11 July 2018 for a period of one year based on the approval accorded by the Board of Trustees of DPT.

5. Since the amendment in the effective date of implementation of rationalization of storage charge prescribed in the Order dated 24 July 2019 proposed by the VPT is mutually agreed between the VPT and VGCBPL, approved by the Board of Trustees of the VPT and is based on directives of the MOPSW, this Authority amends the effective date of rationalized storage charges approved vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 as 11 July 2018 as now proposed by the Port. The validity of the rationalized storage charge approved in the said Order i.e. till 20 January 2020 shall remain unchanged.

6.1. In the result, and for the reason given above, and based on a collective application of mind, this Authority amends the effective date of the rationalized storage schedule approved by this Authority vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 as 11 July 2018 and replaces with the following schedule:

(in ₹ per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Particulars	Storage Charges applicable for the year 2018-19 after applicable indexation	Existing Storage Charges applicable for the year 2019-20 after applicable indexation	Amended Storage Charges from 11.07.2018 till 31.3.2019	Amended Storage Charges from 1.4.2019 till 20.1.2020
1.	Storage Charges (0-10 days)	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
2.	Storage Charges (11-15 days)	2.06	2.11	No Charges	No Charges
3.	Storage Charges (16-20 days)	4.11	4.21	No Charges	No Charges
4.	Storage Charges 21 <sup>st</sup> Day onwards	8.22	8.43	8.22	8.43

”

6.2. The notes prescribed under the schedule in the Order dated 24 July 2019 remains the same.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty. 313/21-22]